भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 994

उत्तर देने की तारीख 2 दिसंबर, 2024

सोमवार, 11 अग्रहायण 1946 (शक)

भारतीय कार्यबल में कौशल अंतर

994. श्री शंकर लालवानी: श्री कंवर सिंह तंवर: श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल: श्री बिप्लब कुमार देब: डॉ. भोला सिंह:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ भागीदारी करके भारतीय कार्यबल में व्यापक कौशल की कमी को दूर करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार स्नातक छात्रों को प्रौद्योगिकी आधारित कोई पाठ्यक्रम प्रदान करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या वर्ष 2014 से विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में युवाओं की रोजगार क्षमता में कोई उल्लेखनीय सुधार हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) का उद्देश्य कार्यबल में कौशल की कमी को दूर करना है। सिम का उद्देश्य विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के माध्यम से युवाओं को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रदान करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय कार्यबल में कौशल की कमी को दूर किया जा सके। सिम का उद्देश्य देश के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार और उद्योग के लिए तैयार कौशल प्रदान करना है।

(ख) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, सरकारी स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कौशल केंद्रों की स्थापना करके, अल्पावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचे के साथ व्यावसायिक और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। पहुँच को बढ़ाने के लिए डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल और मिश्रित प्रशिक्षण प्रारूप अपनाए जा रहे हैं। स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) डिजिटल सामग्री और ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए एक भंडार के रूप में कार्य करता है। इन पहलों का उद्देश्य युवाओं को वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य में उच्च मांग वाली भूमिकाओं के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में 29 आधुनिक युग या भावी कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

(ग) नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस 2023-24) अनुमानों के अनुसार, भारत में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 में 17.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 10.2 प्रतिशत रह गई है; और उत्तर प्रदेश राज्य में यह वर्ष 2017-18 में 16.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 9.1 प्रतिशत रह गई है।

*****